

1) 1 जुलाई 2026 से VB-G RAM G लागू

विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) 1 जुलाई 2026 से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हुआ और इसने MGNREGA का स्थान लिया। इस नई व्यवस्था के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का मजदूरी आधारित रोजगार सुनिश्चित किया गया है। +1

परीक्षा में महत्व: ग्रामीण विकास, शासन, योजनाओं की तुलना, तथा सामाजिक न्याय से जुड़े प्रश्नों में अत्यंत महत्वपूर्ण।

2) मध्यप्रदेश को योजना में बड़ा आवंटन

VB-G RAM G के अंतर्गत मध्यप्रदेश को 2026–27 के लिए ₹6,252.03 करोड़ की अंतरिम राशि तथा ₹630.76 करोड़ की पहली किस्त मिली। यह राज्य-विशिष्ट तथ्य MPPSC में सीधे पूछा जा सकता है।

परीक्षा में महत्व: राज्य वित्त, ग्रामीण रोजगार और योजना-क्रियान्वयन संबंधी प्रश्नों के लिए उपयोगी।

3) Modified UDAN का शुभारंभ

Modified UDAN योजना 4 जुलाई 2026 को शुरू हुई और यह FY 2026–27 से FY 2035–36 तक चलेगी, जिसका कुल परिव्यय ₹28,840 करोड़ है। इसके तहत 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलिपैड विकसित किए जाने हैं।

परीक्षा में महत्व: अधोसंरचना, परिवहन, क्षेत्रीय संपर्क और संतुलित विकास पर प्रश्नों के लिए उपयोगी।

4) जल संरक्षण अभियान पर जोर

4 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक जल संचय जनभागीदारी: Catch the Rain अभियान चलाया गया, जिसमें वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जलाशयों के पुनर्जीवन और जनभागीदारी पर जोर दिया गया। यह मध्यप्रदेश की भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों से सीधे जुड़ता है।

परीक्षा में महत्व: भूगोल, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जल संसाधन के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

5) मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद के प्रमुख निर्णय

जुलाई 2026 में मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद ने नगरीय अधोसंरचना के लिए ₹8,445 करोड़, कुंडालिया प्रमुख सिंचाई परियोजना हेतु ₹245.45 करोड़, तथा मूंग खरीदी के लिए ₹1,587 करोड़ की सरकारी गारंटी को मंजूरी दी। ये निर्णय राज्य की विकास प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं।

परीक्षा में महत्व: मध्यप्रदेश अर्थव्यवस्था, कृषि, सिंचाई, कल्याणकारी नीतियों और शासन से जुड़े प्रश्नों के लिए अत्यंत उपयोगी।

6) डिजिटल गवर्नेंस में प्रगति

मध्यप्रदेश ने State Data Centre 3.0, AI/ML आधारित बिज़नेस इंटेलिजेंस, चैटबॉट, ड्रोन सेवाएँ, ई-साइन और GIS आधारित प्रशासनिक प्रणालियों पर कार्य आगे बढ़ाया। यह प्रशासनिक आधुनिकीकरण का उदाहरण है।

परीक्षा में महत्व: ई-गवर्नेंस, प्रशासनिक सुधार और सुशासन के मुख्य परीक्षा उत्तरों में उपयोगी।

7) मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा

राज्य में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत इंदौर क्षेत्र से सार्वजनिक परिवहन को नई शुरुआत दी गई और प्रथम चरण में 150 इलेक्ट्रिक बसों की योजना बनाई गई। यह हरित परिवहन और शहरी सेवा प्रदाय का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

परीक्षा में महत्व: शहरीकरण, सार्वजनिक परिवहन, पर्यावरण-अनुकूल नीतियों और राज्य शासन के प्रश्नों में उपयोगी।

8) MPPSC में पारदर्शिता की दिशा में कदम

MPPSC ने 2019 से 2024 तक की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की वर्णनात्मक उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण की अनुमति चरणबद्ध रूप से नवंबर 2026 से देने की घोषणा। इससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता का संकेत मिलता है।

परीक्षा में महत्व: साक्षात्कार, निबंध तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता पर आधारित प्रश्नों में उपयोगी।

9) दतिया विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना

निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई 2026 को मध्यप्रदेश की 22-दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव की अधिसूचना जारी की। मतदान 30 जुलाई 2026 और मतगणना 3 अगस्त 2026 के लिए निर्धारित की गई थी।

परीक्षा में महत्व: मध्यप्रदेश की समसामयिक राजनीति और निर्वाचन आयोग संबंधी तथ्यों के लिए महत्वपूर्ण।

10) मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी

15 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹62,500 करोड़ के परिव्यय वाली Mobile Phone Manufacturing Scheme को मंजूरी दी। यह योजना विनिर्माण, घरेलू मूल्य संवर्धन और भारतीय ब्रांड निर्माण को प्रोत्साहन देती है।

परीक्षा में महत्व: अर्थव्यवस्था, औद्योगिक नीति, Make in India और विनिर्माण क्षेत्र के प्रश्नों में उपयोगी।

11) Semicon 2.0 को स्वीकृति

15 जुलाई 2026 को Semicon 2.0 को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली। यह भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक नीति समर्थन को दर्शाता है।

परीक्षा में महत्व: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, औद्योगिक आत्मनिर्भरता और रणनीतिक विनिर्माण से जुड़े प्रश्नों में उपयोगी।

12) National Investment Policy for Urea-2026

की 15 जुलाई 2026 की सूची में National Investment Policy for Urea-2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी दर्ज की गई। यह उर्वरक उत्पादन, कृषि इनपुट सुरक्षा और घरेलू विनिर्माण से जुड़ा महत्वपूर्ण नीति कदम है।

परीक्षा में महत्व: कृषि, उर्वरक नीति, खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नों के लिए उपयोगी।

13) PMGKAY के तहत बेहतर गुणवत्ता वाले चावल की स्वीकृति

सरकार ने PMGKAY के अंतर्गत बेहतर गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति को मंजूरी दी, जिससे 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बेहतर गुणवत्ता का खाद्यान्न मिलेगा। यह कल्याणकारी योजनाओं में गुणवत्ता-आधारित सुधार को दर्शाता है।

परीक्षा में महत्व: खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर प्रश्नों में उपयोगी।

14) भारत-इज़राइल द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू

भारत-इज़राइल Bilateral Investment Agreement 4 जुलाई 2026 से लागू हुआ। यह भारत की आर्थिक कूटनीति और निवेश संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है।

परीक्षा में महत्व: अंतरराष्ट्रीय संबंध, व्यापार और विदेशी निवेश आधारित प्रश्नों में उपयोगी।

15) PLI योजनाओं की प्रगति

Reforms Utsav & Chintan Shivir 2026 में बताया गया कि PLI योजनाओं ने ₹2.40 लाख करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित किया और 14.15 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए। यह नीति-आधारित औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण संकेतक है।

परीक्षा में महत्व: अर्थव्यवस्था, रोजगार, औद्योगिक विकास और नीति-विश्लेषण से जुड़े प्रश्नों में अत्यंत उपयोगी।